Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा हाईपावर वर्किंग कमेटी मीटिंग में गुरुग्राम के लिये 155 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट मंजूर 3
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने किया कनाडा के साथ एमओयू 3
- अनुपमा उपाध्याय बनी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की विजेता 3
- टोनी ब्लेयर फाउंडेशन और हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर करेगी काम 4
- पंचकूला में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत 4
- हरियाणा में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू 5
- 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास' 6
- हरियाणा कृषि विकास मेला - 2023 6
- व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना (सीसीएचआईएस) तैयार 7
- वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक 7
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह 8
- हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 8
- 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023 9
- ब्लॉक परिवर्तन योजना 10
- भिवानी में 298.44 करोड़ रुपए के पीएमईजीपी ऋण स्वीकृत 10
- इंटरएक्टिव डिजिटल ई-फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन 11
- 'दयालु योजना' 12
- प्रदेश सरकार ने पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय का नाम बदला 13
- हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक ने तीन पुस्तकों का विमोचन किया 14
- झज्जर की पूजा ने एशियाई खेलों के लिये किया क्वालीफाई 14
- मुख्यमंत्री ने जारी की हरियाणा की गतिशील भू-जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट 15
- अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ 15
- 20वां CSI SIG e-Governance Awards-2022 16
- राशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र के बारे में अधिसूचना जारी 17
- 'पदमा' में स्थापित होगा वेंचर कैपिटल फंड 18
- हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये बनाए जाएंगे 1 लाख घर 19
- डॉ. विजय चावला की टीम ने बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में जीते 3 अवॉर्ड 20
- हिसार को मिली 19742.49 लाख रुपए की 93 परियोजनाओं की सौगात 21

नोट :

हरियाणा

हरियाणा हाईपावर वर्किंग कमेटी मीटिंग में गुरुग्राम के लिये 155 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट मंजूर

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्किंग कमेटी में प्रदेश के गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की लगभग 155 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पहली बार 10 करोड़ रुपए से अधिक के इंजीनियरिंग कार्यों के आवंटन के लिये हाई पावर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई।
- उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग वर्क्स के लिये पहली बार ई-निविदाएँ आमंत्रित करने के लिये आरंभ किया गया हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है।
- बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम की मुख्य सड़क एमजी रोड का दिल्ली के लोधी रोड की तर्ज पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
- गुरुग्राम के इफको चौक से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक सर्विस लेन, वेंडर ज़ोन तथा बस क्यू शेल्टर को भी नया रूप दिया जाएगा तथा धनवापुर में 100 एमएलडी एसटीपी के निर्माण, वसई व बहरमपुर में सब स्टेशन से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने किया कनाडा के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को हरियाणा के पलवल ज़िले के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने बताया कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने कनाडा के प्रतिष्ठित सस्कैचवन संस्थान के साथ एमओयू किया है।

प्रमुख बिंदु

- कुलपति राज नेहरू ने बताया कि इस एमओयू के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कनाडा के इस संस्थान के साथ कौशल शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण साझेदारी निभाएगा। दोनों संस्थान पाठ्यक्रम और तकनीक में साझेदारी करेंगे और साथ ही फैकल्टी के ज्ञान का भी आदान-प्रदान होगा। ज्वाइंट प्रोग्राम में स्टूडेंट एक्सचेंज भी महत्त्वपूर्ण घटक होगा।
- एमओयू के तहत पाठ्यक्रम, विधि और तकनीक साझा होगी। इसी तरह से विद्यार्थी और शिक्षक भी एक-दूसरे के प्रोग्राम में हिस्सेदारी कर सकेंगे।
- इससे अकादमिक तौर पर विश्वविद्यालय को काफी लाभ होगा। इससे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी और अधिक प्रबल होंगे। यहाँ के विद्यार्थी कनाडा के संस्थान के साथ इंटर्नशिप और ट्रेनिंग को और बेहतर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर कर सकेंगे।

अनुपमा उपाध्याय बनी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की विजेता

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय विजेता बनी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमैन सिंगल में राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी है।
- गौरतलब है कि अनुपमा उपाध्याय ने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप को हराकर पहली बार महिला एकल का खिताब जीता है। अनुपमा ने रोमांचक खिताबी मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आकर्षी को 20-22, 21-17, 24-22 से हराया।
- जूनियर वर्ग में अपने प्रदर्शन के दम पर अनुपमा ने प्रथम रैंक हासिल किया। वर्तमान में इस वर्ग में ऑल वर्ल्ड उनकी तीसरी रैंकिंग है।
- उनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेजिडेंट देवेंद्र सिंह ने विजेता अनुपमा उपाध्याय को पाँच लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है।

टोनी ब्लेयर फाउंडेशन और हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर करेगी काम

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में शिष्टाचार मुलाकात करते हुए स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर परस्पर सहयोग करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- टोनी ब्लेयर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी संस्था टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन हरियाणा मंल स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में और विस्तार होगा तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदृढ़ होंगी।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करवा रही है। प्रदेश के सभी ज़िलों में एक-एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है, जिससे न केवल डॉक्टरों की कमी पूरी होगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएँ भी सुदृढ़ होंगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोनी ब्लेयर को श्रीमद्भगद्वगीता तथा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

पंचकूला में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

4 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश के पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका टाउन पार्क में विधिवत् रूप से 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इस बार के स्प्रिंग फेस्टिवल में फूलों की विभिन्न किस्मों सहित ड्राई फ्लॉवर डेकोरेशन भी आकर्षण का केंद्र है। इस बार आगंतुकों को फ्लोरल ज्वैलरी, सब्जी की नक्काशी, लेजर शो इत्यादि देखने को मिलेगा। बच्चों के लिये विशेष तौर पर कठपुतली शो और मैजिक शो का भी प्रबंध किया गया है।
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा आयोजित 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल में इस बार 1500 से ज्यादा स्कूल, संस्थान और संगठन भाग ले रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि दो दिवसीय आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा हास्य रस सम्मेलन, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, डुएट डांस, मोनो एक्टिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, पॉट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और लोक नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पहली बार हॉट एयर बैलून और आईटीबीपी बैंड भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं।

नोट :

हरियाणा में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू

चर्चा में क्यों ?

5 मार्च, 2023 को हरियाणा जनसंपर्क, सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस ने आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करते हुए केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित परियोजना इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू आईसीजेएस परियोजना को गृह मंत्रालय के जरिये पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है, जिस पर प्रदेश पुलिस आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रही है।
- राज्य के एक पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पुलिस ने आईसीजेएस परियोजना का उपयोग करते हुए 45 वाहनों को ट्रेस करने में, 67 उद्घोषित अपराधियों व बेल जंपर्स और 02 मोस्ट वांटेड अपराधियों को ढूंढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उक्त डेटा पर 4 एफआईआर भी प्रदेश में दर्ज की गई हैं।
- पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आईसीजेएस परियोजना यानी, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पहले चरण में अलग-अलग आईटी सिस्टम को लागू और व्यवस्थित किया गया है। इस सिस्टम को रिकॉर्ड को सर्च करने में भी सक्षम बनाया गया है।
- इसके अलावा चरण-2 के तहत इस सिस्टम को 'एक डेटा, एक एंट्री' के सिद्धांत पर तैयार किया गया है, जिसके तहत डेटा केवल एक कॉलम में केवल एक बार दर्ज किया जाता है और फिर वही डेटा अन्य सभी कॉलम में दर्ज हो जाता है। इसके लिये प्रत्येक कॉलम में डेटा की फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है।
- राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निदेशक ओ.पी. सिंह ने बताया कि आईसीजेएस सिस्टम को हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक डेडिकेटिड और सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये उपलब्ध कराया जा रहा है।
- प्रदेश में आईसीजेएस परियोजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर है।
- इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) मुख्य आईटी सिस्टम के एकीकरण के लिये एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जिसका इस्तेमाल पाँच कॉलम [पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली), फॉरेंसिक लैब के लिये ई-फॉरेंसिक, न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिये ई-प्रॉसीक्यूशन, जेलों के लिये ई-जेल] के जरिये देश में आपराधिक न्याय को लागू करने के लिये किया जाता है।
- इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश पुलिस के पास जेलों में बंद अपराधियों का पूर्ण रिकार्ड रहता है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर में अपराधी का नाम व अन्य सूचना की एंट्री करने से यदि किसी अन्य राज्य में उसकी स्थिति है तो तभी अपडेट हो जाती है। उक्त सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी आगामी कार्यवाही कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक अपराधी कई राज्यों में वांछित होता है और किसी अन्य राज्य में जेल में बंद होता है। ऐसी स्थिति में इस सॉफ्टवेयर पर जो डाटा बेस उपलब्ध है, उसकी सहायता से अपराधियों की वर्तमान लोकेशन को ढूंढा जा सकता है।
- इसके अलावा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से चोरी हुए वाहनों का पता लगा सकते हैं।
- पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सीसीटीएनएस/इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में अच्छी प्रथाओं पर एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में हरियाणा पुलिस ने आईसीजेएस परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 117 एफएसएल और सीएफएसएल के प्रदर्शन का मूल्यांकन एनसीआरबी द्वारा परिभाषित मापदंडों पर किया गया, जिसमें हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर रहा। पूरे वर्ष प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार 20 से अधिक मापदंडों पर प्रदेश प्रथम स्थान पर बना रहा।

नोट :

'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास'

चर्चा में क्यों ?

6 मार्च, 2023 को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि राज्य सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित, मानकीकृत और सरलीकृत दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिये 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास'नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन ने बताया कि 'हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास' लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देने में अहम साबित होगा, इससे विभिन्न बीमा योजनाएँ भी समेकित हो जाएंगी।
- उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिये प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना'बनाई है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके।
- चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में छोटे व्यापारियों के लिये 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना'बनाई गई है, ताकि मुसीबत के समय इनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके।
- इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिये 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना'तैयार की गई है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ देकर उनको चिंतामुक्त किया जा सके।
- चेयरमैन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों और 1.50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के कल्याण के लिये किसी भी प्राकृतिक कारणों या आग के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिये 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना'के संशोधित दिशा-निर्देशों को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है। यह योजना भी 1 अप्रैल, 2023 से पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी।

हरियाणा कृषि विकास मेला - 2023

चर्चा में क्यों ?

6 मार्च, 2023 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के हिसार ज़िले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 10 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के प्रगतिशील किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत करवाने के लिये हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 का आयोजन किया जा रहा है।
- मेले में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी तथा किसानों के मध्य फसल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इसी प्रकार रबी फसलों की नई किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और मिट्टी व पानी के नमूनों की सामान्य शुल्क पर जांच की जाएगी।
- इस मेले में कृषि संबंधित समस्याओं एवं समाधान विषय पर प्रश्नोत्तरी सभा होगी और खरीफ फसलों व सब्जियों के प्रमाणित बीजों की जानकारी दी जाएगी एवं बिक्री की जाएगी।
- प्रवक्ता के अनुसार कृषि विकास मेले में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे। इसके अलावा लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रतिदिन एक छोटा ट्रैक्टर, सुपर सीडर व पावर विंडर मशीन तथा 12 मार्च 2023 को किसानों को बड़ा ट्रैक्टर जीतने का मौका मिलेगा।

नोट :

व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना (सीसीएचआईएस) तैयार

चर्चा में क्यों ?

7 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हुई सीसीएचआईएस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक में बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना (सीसीएचआईएस) तैयार की गई है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष मंज़ूरी के लिये पेश किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इस योजना से बोर्डों और निगमों सहित लगभग 3.35 लाख परिवार (लगभग 14.30 लाख व्यक्ति) कर्मचारी लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा, पेंशनधारकों के 3.05 लाख परिवार (6.10 लाख व्यक्ति), मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के 1200 परिवार (लगभग 4800 व्यक्ति), आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार (848 व्यक्ति), हिन्दी आंदोलन से जुड़े 186 परिवार (372 व्यक्ति), आपातकाल के दौरान जेल में बंद 555 परिवार (1,110 व्यक्ति) और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद 614 परिवार (1228) इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- इस व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुल 6 लाख 52 हज़ार परिवारों (20.48 लाख व्यक्ति) को कवर किये जाने की उम्मीद है।
- स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों से इस योजना के संबंध में टिप्पणियाँ व सुझाव मांगे जा चुके हैं। इनके अलावा विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों निगम, मिनिस्टीरियल एजुकेशन कर्मचारियों के विभिन्न कर्मचारी और पेंशनधारक यूनियनों के भी सुझाव लिये गए।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना का ड्राफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा प्रस्ताव को व्यापक विचार-विमर्श के लिये मुख्य सचिव की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिये रूपरेखा तय करने हेतु चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि 1 अप्रैल, 2023 से ही नई योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करके उसे पुन: उपयोग में लाना महत्त्वपूर्ण परियोजना है, इसलिये ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पावर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये प्लान बनाएँ।
- जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
- बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिये प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा इस वर्ष 70 हज़ार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- बैठक में बताया गया कि म्हारा गाँव-जगमग गाँव योजना के तहत 5694 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शेष गाँवों को भी जल्द इस योजना के तहत लाया जाएगा। यमुनानगर ज़िले में 800 मेगावॉट पावर प्लांट की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष में कार्य आरंभ हो जाएगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने बताया कि आमजन को सुरक्षित, आरामदेय व किफायती परिवहन सेवाएँ मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50 प्रतिशत छूट के लिये आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें।
- अधिकारियों ने बताया कि ई-टिकटिंग प्रणाली सभी ज़िलों में लागू की जा चुकी है। इसके अलावा, 6 बस पोर्ट स्थापित करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है।
- मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन खालों को बने 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनका डाटा एकत्र कर, उनके रखरखाव व मरम्मत के लिये एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिये विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए।
- उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम से पहले भू-जल रिचार्जिंग के लिये रिचार्जिंग बोरवेल बनाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने इस वर्ष के लिये लगभग 2 हज़ार रिचार्जिंग बोरवेल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को हरियाणा जनसंपर्क, सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के करनाल ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि कार्यक्रम में 40 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस अवॉर्डों के लिये बालिका उत्थान हेतु 62 अवॉर्ड दिये गए।
- कार्यक्रम में पहला सुषमा स्वराज अवॉर्ड दिया गया, जिसमें पाँच लाख रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवॉर्ड के तहत 1.50 लाख रुपए की राशि दी गई।
- राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि महिला दिवस समारोह में कल्पना चावला शौर्य अवॉर्ड, लाइफ टाइम अचीवर्स अवॉर्ड, एएनएम/नर्सिज/महिला एमपीडब्ल्यू को पुरस्कार, स्पोर्ट्स वूमेन अवॉर्ड, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता अवॉर्ड, महिला इंटरप्रेन्योर अवॉर्ड, स्त्री शक्ति अवॉर्ड, बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुरस्कार दिये गए।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में हरियाणा में शिक्षा, सांस्कृतिक, सेना, गायन, कला, चिकित्सा, समाज कल्याण, जागृति जागरण, सशक्तीकरण, खेल, पर्वतारोहण, उड़ान समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
- राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशभर से हज़ारों महिलाएँ शामिल हुई, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ भी शामिल हैं। समारोह में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किये गए उत्पादों की विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई।

हरियाणा कृषि विकास मेला-2023

चर्चा में क्यों ?

10-12 मार्च, 2023 तक हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप लॉन्च किये।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिये सहयोग करें और नई विधाओं को आगे लेकर आएँ। इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे खेती में जहाँ कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ-साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि पानी के समुचित उपयोग के लिये सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने हेतु सरकार किसानों को 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा, बरसाती पानी को वापस ज़मीन में डालने के लिये बोरवेल लगाए जा रहे हैं, जिसमें किसान को केवल 25 हज़ार रुपए देने हैं, बाकी खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार पहले चरण में 1 हज़ार रिचार्ज़िंग बोरवेल लगाएगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख एकड़ भूमि खेती योग्य है, इस भूमि की एक-एक इंच का विवरण तैयार किया जा रहा है। इसके लिये किसान अपनी फसल का पूरा विवरण 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपलोड करें। राज्य में किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिये एफपीओ गठित किये जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा पहला प्रदेश है, जो 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत किसानों को एमएसपी और खरीद मूल्य के अंतर को भी किसानों को दिया जा रहा है।
- कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहली बार प्रदेश में हरियाणा सरकार ने राजस्थान की सीमा के साथ लगते 300 टेलों, जहाँ पिछले 25 साल से पानी नहीं पहुँचा था, वहाँ भी पानी पहुँचाया है।
- इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने बताया कि हर बार कृषि विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिन का यह मेला आयोजित किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस मेले के स्वरूप को बढ़ाने के क्रम में कृषि विभाग, सीआईआई के साथ-साथ आने वाले वक्त में विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी संस्थाओं की भी मेले में भागीदारी होगी।
- उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों का बजट, जो वर्ष 2014 में 20 से 25,000 करोड़ रुपए था, उसको इस वर्ष छह गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए किया है।
- इस बार के बजट में भी मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिये 40 करोड़ रुपए के बजट को 400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत लगभग 6000 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। इसके अलावा, जो किसान फसल बीमा योजना में कवर नहीं थे, उनकी फसल खराब होने पर भी लगभग 4000 करोड़ रुपए मुआवज़ा दिया गया है।

39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023

चर्चा में क्यों ?

12 से 14 मार्च, 2023 तक हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में तीन दिवसीय 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी-2023 के समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पशुओं की देखभाल हेतु प्रदेश में छह पॉलीक्लीनिक बनाए जाएंगे। चरखी दादरी में भी एक पॉलीक्लिनिक बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं।
- इसके अलावा, प्रदेश में गौवंश की देखभाल के लिये गौ-सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा बढ़ोतरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट साँझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की ज़मीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक, जिनके पास अपने पशु बाँधने के लिये जगह नहीं है, वे इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तथा 1 अप्रैल, 2023 को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिये कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया है। हरियाणा में 632 गौशालाएँ हैं।
- राज्य में गौ-सेवा आयोग का गठन किया गया है। बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिये बजट में वृद्धि की गई है। इसमें उन गौशालाओं को अधिक बजट दिया जाएगा, जो बेसहारा गौवंश की देखभाल करेंगी। पंचायत या अन्य संस्थाएँ भी गौशाला बनाकर पशुओं की देखभाल करेंगी, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि गाय का ए-टू दूध बहुत लाभकारी है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ दूर होती हैं। इसका अनुसंधान भी करवाया गया है। ए-टू दूध के सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है व अन्य गंभीर बीमारियों में भी यह लाभकारी है।

नोट :

- इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जे.पी. दलाल ने बताया कि इस प्रकार के मेले आयोजित करने का उद्देश्य किसानों व पशुपालकों को नई-नई तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि इन तकनीकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर उनकी आमदनी को बढ़ाना है।
- उन्होंने बताया कि गौ-सेवा आयोग की नीति है कि प्रदेश के 22 ज़िलों में एक गौ वन बने, जहाँ इन पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। हरियाणा अकेला प्रदेश है, जहाँ 8 लाख से ज़्यादा पशुओं का बीमा किया गया है।
- जे.पी. दलाल ने बताया भारत सरकार की नीतियों के अनुसार प्रदेश में एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पशुपालक कॉल करके एंबुलेंस की मांग कर सकेंगे। उसके बाद तुरंत नजदीकी एंबुलेंस पशुपालक के घर जाएगी। पहले चरण में 70 एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। बाद में 200 एंबुलेंस होंगी।
- पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरोगेटरी तकनीक से बछड़िया पैदा करने में सफलता हासिल की है। इसी प्रकार भैंस अनुसंधान द्वारा क्लोन से झोटा पैदा करने में भी सफलता हासिल की है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा।

ब्लॉक परिवर्तन योजना

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान करने और उसे विकसित करने के लिये 'ब्लॉक परिवर्तन योजना' लेकर आई है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य में अविकसित ब्लॉकों की पहचान करने हेतु 18 प्रतिबद्धता तथा 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को अंतिम रूप दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक ज़िले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जा रही है तथा गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचे व शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता एवं अधिकारिता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि एवं सिंचाई सहित विभिन्न केपीआई के आधार पर कार्य शुरू किया जाएगा।
- विभाग द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर इन केपीआई की मासिक और त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
- मुख्य सचिव ने बताया कि चयनित खंडों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी तथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को पुरस्कृत किया जाएगा।

भिवानी में 298.44 करोड़ रुपए के पीएमईजीपी ऋण स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

14 मार्च, 2023 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत 2989 लाभार्थियों के लिये 16 करोड़ रुपए का मार्जिन मनी अनुदान जारी किया। इन लाभार्थियों को हरियाणा के भिवानी ज़िले में स्थित झुंपा में पीएमईजीपी के तहत उद्यम स्थापित करने के लिये बैंकों द्वारा 298.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि लाभार्थियों की ओर से स्थापित इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 24,000 लोगों को अतिरिक्त रोज़गार प्राप्त होगा। इसके अलावा हरियाणा के पीएमईजीपी लाभार्थियों को 67 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण के बदले 4.44 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी अनुदान धनराशि भी वितरित की गई।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम-(पीएमईजीपी)' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत'के सपने को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केवीआईसी अपनी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में कारीगरों के लिये उनके घर में ही बहुत कम लागत पर रोज़गार के अवसर सृजित कर रहा है।
- इस अवसर पर चर्म कारीगरों के लिये अधिकारिता कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 50 लाभार्थियों को फुटवियर निर्माण के लिये उन्नत टूल-किट ऑनलाइन माध्यम के जरिये वितरित की गईं।
- इसके अलावा केवीआईसी की 'शहद मिशन'योजना के तहत हरियाणा के 40 प्रशिक्षित लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिये 400 मधुमक्खी-बक्से भी ऑनलाइन वितरित किये गए।
- मनोज कुमार ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक कारीगरों को टूल किट उपलब्ध कराकर उनके कौशल उन्नयन और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ जा सके।
- विदित है कि पीएमईजीपी योजना के तहत भारत सरकार ने परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।
- इन पीएमईजीपी इकाइयों को स्थापित करने के लिये सरकार शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को अनुदान के रूप में पूरी परियोजना लागत का 15 फीसदी से 25 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी से 35 फीसदी हिस्सा प्रदान करती है।
- इसके अलावा ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को उनके चुने हुए उद्यम की स्थापना के संबंध में नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

इंटरएक्टिव डिजिटल ई-फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन

चर्चा में क्यो ?

15 मार्च, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक अवार्डी डॉ. विजय कुमार चावला द्वारा गणित दक्षताओं को विकसित करने लिये तैयार इंटरएक्टिव डिजिटल ई-फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान कौशल विकसित करने में डिजिटल ई-फ्लिप बुक तथा फ्लैश कार्ड खेल पिटारा किट मील का पत्थर साबित होगी।
- कंवरपाल ने कहा कि आज के आधुनिक डिजिटल युग में 'निपुण भारत मिशन'के तहत छात्रों में संख्यात्मकता और उससे संबंधित अवधारणाओं की बुनियादी समझ और दक्षता विकसित करने के लिये गेमीफिकेशन तकनीक बेहतरीन तकनीकों में से एक है।
- उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित बुनियादी समझ और दक्षताएँ विकसित करने के लिये डिजिटल तथा ऑफलाइन गणित खेलों की डिजिटल इंटरैक्टिव ई-फ्लिप बुक में 32 खेल शामिल किये गए हैं।
- विद्यार्थी डिजिटल तथा ऑफलाइन खेलों के माध्यम से खेल-खेल में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक उद्देश्यों- जोड़-घटा, भाग तथा गुणा करना जैसी विभिन्न दक्षताओं का आकलन स्वयं कर पाएंगे।
- शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटरैक्टिव डिजिटल ई-फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड पिटारा में डिजिटल और ऑफलाइन गेम दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किये गए हैं। ये सभी खेल ध्यान विकार वाले विद्यार्थियों के लिये वास्तव में लाभदायक सिद्ध होंगे।
- इन खेलों को खेलने के लिये विद्यार्थियों को दिये गए गेम के लिंक पर क्लिक करना होगा या क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। विद्यार्थी इन खेलों को खेलकर आसानी से संख्यात्मकता और उससे संबंधित अवधारणाओं की बुनियादी समझ और कौशल हासिल कर सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि बहुत जल्द डिजिटल और ऑफलाइन गेम्स की इंटरैक्टिव डिजिटल ई-फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड पिटारा किट एस. सी.ई.आर.टी., गुरुग्राम की वेबसाइट के माध्यम से मुफ्त ओपेन एजुकेशनल रिसोर्स के रूप में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जाएगी।

नोट :

'दयालु योजना'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्तरूप देने की कड़ी में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'दयालु योजना'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 'दयालु योजना'के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है।
- न्यास द्वारा तीन योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिये 'मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना', छोटे कारोबारियों के लिये दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिये 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' शामिल हैं।
- 'दयालु योजना'का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
- विदित है कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
- दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)' और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)' के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी।
- इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी-

आयु वर्ग	बजट घोषणा के	पीएमजेजेबीवाई में	पीएमएसबीवाई में	न्यास द्वारा दी जाने
5 से 12 वर्ष तक	अनुसार मुआवज़ा	मुआवज़ा (18-50)	मुआवज़ा (18-70)	वाली मुआवज़ा राशि
12 से अधिक व 18 वर्ष तक	(2023-24)	....	....	आकस्मिक मृत्यु व
18 से अधिक व 25 वर्ष तक	1 लाख रुपए	....	....	स्थायी दिव्यांगता
25 से अधिक व 40 वर्ष तक	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	1 लाख रुपए
40 से अधिक व 50 वर्ष तक	3 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए
50 से अधिक व	5 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	1 लाख रुपए
70 वर्ष से अधिक	2 लाख रुपए	....	2 लाख रुपए	3 लाख रुपए
5 से 12 वर्ष तक	2 लाख रुपए	....	....	....

नोट :

12 से अधिक व 18 वर्ष तक	2 लाख रुपए	....	....	2 लाख रुपए (केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामले में)
18 से अधिक व 25 वर्ष तक	3 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए
25 से अधिक व 40 वर्ष तक	5 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	3 लाख रुपए
40 से अधिक व 50 वर्ष तक	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	....
50 से अधिक व	2 लाख रुपए	....	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए (केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामले में)
70 वर्ष से अधिक	2 लाख रुपए	....	....	2 लाख रुपए

प्रदेश सरकार ने पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय का नाम बदला

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया। पारित विधेयक के अनुसार, अब पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम के आगे पंडित के स्थान पर दादा शब्द का प्रयोग होगा।

प्रमुख बिंदु

- रोहतक स्थित पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय अब दादा लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा।
- इसी प्रकार, विधानसभा में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया। अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रबंधन प्रणाली के ऑनलाइन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिये, 1975 के अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए हैं।
- इनमें विक्रय, व्यापार, नीलामी तंत्र के माध्यम से टीडीआर प्रमाण-पत्र का हस्तांतरण व विक्रय को संभव बनाने और क्रेता की भौगोलिक स्थिति पर अनजाने में लगाए गए प्रतिबंध को सुधारने के लिये धारा 2 के खंड (एन-2) में संशोधन किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सदन में हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया गया। सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
- पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक 5 अगस्त, 2014 को हरियाणा अधिनियम संख्या 24 के माध्यम से चार सरकारी तकनीकी संस्थानों, अर्थात् राज्य ललित कला संस्थान (SIFA), राज्य डिजाइन संस्थान (SID), राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान (SIFT) तथा राज्य नगरीय योजना और वास्तुकला संस्थान (SIUPA) को एकीकृत करके अस्तित्व में आया।
- इस विश्वविद्यालय की स्थापना डिजाइन, ललित कला, फिल्म और टेलीविजन, नगरीय योजना और वास्तुकला के नये मोर्चों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को सुगम बनाने तथा प्रोत्साहित करने और इन क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये की गई थी।
- ये चारों संस्थान 240 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2011 में शुरू हुए थे तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध थे। राज्य सरकार इन संस्थानों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान कर रही थी।

नोट :

- पंडित लख्मी चंद की दादा लख्मी चंद के रूप में लोकप्रियता को देखते हुए, अब सरकार ने पुन: विश्वविद्यालय का नाम दादा लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक के रूप में करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक ने तीन पुस्तकों का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

19 मार्च, 2023 को हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने पंचकूला स्थित साहित्य अकादमी भवन में साहित्यकार व छायाकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान की नव प्रकाशित पुस्तक 'पगडंडियों का सफर'तथा लेखक, कवयित्री डॉ. सुमन कादयान की दो पुस्तकों 'हरियाणवी मुहावरे व लोकोक्तियाँ' और 'माटी की खुसबू'(हरियाणवी कविताओं) का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने बताया कि साहित्यकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान का यात्रा वृतांत संग्रह 'पगडंडियों का सफर'पाठकों को घर बैठे देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, हिमालय की दुर्गम, खूबसूरत घाटियों की यात्राएँ करवाएगा तथा मरुस्थल की खूबसूरती तथा समुद्र की विशालता का अहसास करवाएगा।
- उन्होंने बताया कि डॉ. सुमन कादयान की पुस्तक 'माटी की खुशबू'हरियाणवी लोक भाषा को समृद्ध करने में सहायक होगा तो 'हरियाणवी मुहावरे व लोकोत्तियाँ'पुस्तक हरियाणवी लोक साहित्य से परिचित करवाएगी।

झज्जर की पूजा ने एशियाई खेलों के लिये किया क्वालीफाई

चर्चा में क्यों ?

18-20 मार्च, 2023 तक महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी छत्रपति स्टेडियम में हुई राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप में हरियाणा के झज्जर ज़िले के गाँव रेढ़ूवास की निवासी पूजा मोर ने तीन सिल्वर मेडल जीतकर एशियाई खेल-2023 के लिये क्वालीफाई किया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप में पूजा मोर ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक, 1500 मीटर दौड़ में रजत और लंबी कूद में भी रजत पदक जीते हैं।
- विदित है कि पूजा अपने कोच आशीष छिकारा के मार्गदर्शन में लगातार तीन वर्षों से नेशनल चैंपियन रही हैं। 2021 में उसने तीन स्वर्ण पदक जीत थे। वहीं, वर्ष 2022 में 2 स्वर्ण व एक रजत हासिल किये। इससे पहले पूजा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 400 मीटर दौड़ में ट्यूनीशिया में हुई प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया था।
- उल्लेखनीय है कि एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक चार वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु-खेल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस वर्ष के एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित किये जाएंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने जारी की हरियाणा की गतिशील भू-जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भू-जल प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से 31 मार्च, 2022 तक तैयार की गई हरियाणा की गतिशील भू-जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- राज्य की गतिशील भू-जल संसाधन क्षमता रिपोर्ट में 141 ब्लॉक और गुरुग्राम एवं फरीदाबाद के दो शहरी क्षेत्रों जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, का आकलन किया गया है।
- हरियाणा सरकार के प्रयासों से भूगर्भ जल संसाधन आकलन, 2022 के अनुसार भूजल के विकास के स्तर में सुधार हुआ है। वर्ष 2020 के दौरान प्रदेश में औसतन भू-जल दोहन का स्तर 134.56 प्रतिशत था, जो 2022 के दौरान कम होकर 134.14 प्रतिशत हो गया है।
- यह रिपोर्ट केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा विकसित इन-जीआरईएस सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई है।

अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

25 मार्च, 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले के टिकली गाँव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 'अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाँच राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के लगभग 5 किमी. के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है।
- कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वानिकी के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिये एक कार्ययोजना और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा कृषि वानिकी पर प्रकाशित एफएक्यू का अनावरण किया।

नोट :

- अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के तहत वनरोपण, पुन: वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा।
- यह परियोजना स्थानीय समुदायों को रोज़गार के अवसर, आय सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करके लाभान्वित करेगी।
- हरियाणा में अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में, परियोजना के तहत 75 जल स्रोतों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 25 मार्च को अरावली परिदृश्य के प्रत्येक ज़िले में पाँच जल स्रोतों से हुई ।
- परियोजना में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान और जल संसाधनों का संरक्षण भी शामिल होगा। यह परियोजना गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िलों में बंजर भूमि को शामिल करेगी।
- स्वैच्छिक संगठन, सोसाइटी फॉर जियोइन्फॉर्मेटिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनजीओ, आईएमगुरुग्राम क्रमश: बंधवाड़ी और घाटबंध में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिये श्रमदान के उद्देश्य से लोगों को जुटाने के काम में लगे हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट केंद्रीय वन मंत्रालय के भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का हिस्सा है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्य शामिल हैं जहाँ 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अरावली की पहाड़ियाँ फैली हैं।
- इस परियोजना में तालाबों, झीलों और नदियों जैसे सतही जल स्रोतों के कायाकल्प और पुनर्स्थापन के साथ-साथ झाड़ियों, बंजर भूमि और खराब वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की मूल प्रजातियों को लगाना शामिल होगा।
- यह परियोजना स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिये कृषि वानिकी और चरागाह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - अरावली रेंज के पारिस्थितिकी सेहत में सुधार।
  - थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने और हरित बाधाओं को बनाकर भूमि क्षरण को कम करना, जो मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों को रोकेंगे।
  - यह हरित दीवार अरावली क्षेत्र में देशी वृक्ष प्रजातियों को लगाकर, वन्यजीवों के लिये आवास प्रदान करके तथा पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करके अरावली रेंज की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिये कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करेगी।
  - वनीकरण, कृषि-वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों से स्थानीय समुदायों को जोड़कर सतत् विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना जिससे आय, रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक लाभ सामने आएंगे।
  - इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों, वन विभागों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और स्थानीय समुदायों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त वित्तपोषण, तकनीकी कौशल, नीति समन्वय और जन-जागरूकता आदि पर काम किया जाएगा।
  - यूएनसीसीडी (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू काम्बैट डायवर्सिफिकेशन), सीबीडी (कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी) और यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेशन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के लिये योगदान करना।
  - पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास में वैश्विक लीडर के रूप में भारत की छवि को आगे बढ़ाना।

20वां CSI SIG e-Governance Awards-2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में केंद्र सरकार की 'कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया' के 20वें CSI SIG e-Governance Award-2022 के तहत हरियाणा के सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग को 'Award Of Appreciation' तथा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि उक्त अवॉर्ड 25 मार्च, 2023 को सीएसआई एसआईजी की ओर से नई दिल्ली के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदान किये गए।
- प्रोजेक्ट केटेगरी के तहत दिए गए अवॉर्ड 'Award Of Appreciation' को हरियाणा के सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग की ओर से उपनिदेशक उर्वशी रंगारा ने प्राप्त किया।
- उर्वशी रंगारा ने बताया कि यह अवॉर्ड विभाग द्वारा मीडिया हाउसेज को जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के लिये आरंभ की गई पहल 'ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर एंड बिलिंग सिस्टम' के लिये मिला है।
- विदित है कि करीब सवा तीन वर्ष पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी पहल करते हुए मीडिया हाउसेस को जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर लॉच किया था।
- इस सॉफ्टवेयर से रिलीज ऑर्डर व विज्ञापन संबंधी भुगतान आसान हुआ। समूची प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो गई, जिससे कार्य में तेज़ी और पारदर्शिता आई।
- इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसे एनआईसी के सहयोग से पूरी तरह से 'इन हाउस' विकसित किया गया है।
- राज्य के सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के अलावा हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन सुचारु रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवदनों पर एकीकृत प्रणाली अपनाने पर सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2022 जीता।
- इसे शहरी स्थानीय निकाय 2022 के आम चुनावों के दौरान एनआईसी हरियाणा द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया था।
- यह पुरस्कार कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया और हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत के साथ हरियाणा राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी दीपक बंसल ने ग्रहण किया।
- इस आईसीटी परियोजना को एनआईसी हरियाणा द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था।
- हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के लिये आईसीटी एप्लीकेशन सूट के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव करवाना था। किसी भी समयबद्ध सार्वजनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिये यह आईसीटी सबसे उपयुक्त है।
- आईसीटी परियोजना में वेब आधारित एकीकृत मॉड्यूल और एप्लिकेशन, मतदाता सूची और वार्ड बंदी तैयार करना, वोटर्स सर्च वेब एप्लिकेशन, चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिये कर्मचारियों के डाटा का ऑनलाइन संग्रह करना, नामांकित उम्मीदवारों के विवरण को कैप्चर करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे जानना (केवाईसी), चुनाव ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली आवेदन, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामें (नामांकन की जाच और नामांकन वापस लेने के बाद), चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये चुनाव चिह्नों का आवंटन, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी तथा प्रबंधन प्रणाली जैसी ऑनलाइन मतगणना परिणाम और कई तरह की रिपोर्ट ई-डैशबोर्ड पर तैयार करना शामिल हैं।

राशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र के बारे में अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राजन गुप्त की अध्यक्षता में गठित राशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र के बारे में अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिये की जाएगी। हालाँकि, उनका कार्यकाल राज्य सरकार के विवेक पर 3 महीने के लिये और अधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- राशनलाइजेशन आयोग के अध्यक्ष का पद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष होगा तथा इस आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़/पंचकूला में होगा।

नोट :

- राशनलाइजेशन आयोग एक स्वायत्त और स्व-नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा। संबंधित विभाग, जिसके संबंध में आयोग राशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा, के प्रशासनिक सचिव को उस विभाग के राशनलाइजेशन के प्रयोजन के लिये आयोग के सदस्य के रूप में सहयोजित माना जाएगा। वह संबंधित विभाग के राशनलाइजेशन के उद्देश्य से आयोग के विचार-विमर्श में पूरी तरह से भाग लेंगे।
- राशनलाइजेशन आयोग के सुचारु कामकाज के लिये अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार राशनलाइजेशन आयोग के लिये अपेक्षित पदों को मंज़ूर करेगी। पदों को आयोग द्वारा विभिन्न तरीके से भरा जा सकता है। राज्य के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम से प्रतिनियुक्ति पर और हरियाणा राज्य के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत्त व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है।
- इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशों और नीतियों के अनुसार कॉन्ट्रैक्चुअल रोज़गार के माध्यम से भी पदों को भरा जा सकता है।
- आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसे सरकार के विवेक पर 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और यथाशीघ्र एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि सरकार उचित समझती है तो, सरकार अपने विवेक से आयोग के कार्यकाल को इसी प्रकार से और अवधि के लिये बढ़ा सकती है।
- आयोग के कार्य-
  - आयोग सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से कर्मचारियों की संख्या के युक्तिकरण के लिये विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन के लिये सिफारिशें करेगा।
  - इसी प्रकार, प्रत्येक विभाग, बोर्ड और निगम के स्वीकृत भरे हुए एवं रिक्त पदों की समीक्षा करना और उनके युक्तिकरण के लिये सिफारिशें करना, विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के मुख्यालय के साथ-साथ फील्ड स्तर पर संगठनात्मक संरचना का अध्ययन करना और उन्हें अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिये सिफारिशें करना, सरकारी विभागों/बोर्डों और निगमों की दक्षता में सुधार के लिये और सभी स्तरों के अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिये आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों की शुरुआत की सिफारिश करना शामिल हैं।
  - विभिन्न विभागों के कर्त्तव्यों और कार्यों के चार्टर की तैयारी के लिये सिफारिशें करना और ऐसे कर्त्तव्यों और कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिये उचित प्रशासनिक संरचना का सुझाव देना भी आयोग के कार्यों में शामिल है।
  - इसके अलावा, हरियाणा राज्य में सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिये भी आयोग कोई अन्य सिफारिश कर सकता है।
- आयोग की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व-
  - आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा और यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगा और अपने स्वयं के कामकाज को विनियमित करेगा। आयोग अपने कामकाज का रिकॉर्ड रखेगा।
  - आयोग के पास किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम से किसी भी प्रकार की जानकारी मांगने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी, जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या, भरे हुए, रिक्त, और ऐसे पदों के विरुद्ध नियोजित कर्मचारियों के प्रकार, पिछले वर्षों के दौरान किये गए बजटीय प्रावधान और वास्तविक व्यय सहित विभाग का बजट, संपूर्ण या किसी विशेष स्तर/क्षेत्रीय संगठन आदि के रूप में विभाग के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति, विभाग द्वारा संभाले जा रहे विषयों से संबंधित कानून, नियम और निर्देश तथा आयोग द्वारा अपने विचार-विमर्श के लिये प्रासंगिक मानी गई कोई अन्य जानकारी शामिल है।
  - यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम, 2016 या उसके लिये लागू किसी भी संबंधित नियम के तहत सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता के लिये कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होगा।

'पदमा' में स्थापित होगा वेंचर कैपिटल फंड

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की तरह 'पदमा'(प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, ताकि 'वन ब्लॉक

नोट :

वन प्रोडक्ट' के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने 'पदमा'को लागू करने के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीति के बारे में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी ली और उसमें सुधार के लिये कई अहम सुझाव भी दिये।
- उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार 'पदमा'के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की 'पदमा'योजना के तहत 'वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट' पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है।
- हाल ही में पेश किये गए बजट में भी अगले 5 वर्षों में 'पदमा'के लिये 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिससे डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किये जाएंगे।
- प्रदेश में जहाँ युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये इक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं 'पदमा'के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा।
- राज्य में 'पदमा'के तहत उद्योग लगाने हेतु करीब दो दर्जन स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉक में जगहों को अंतिम रूप देकर लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा 'पदमा'के लिये 6 स्कीमें बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न इंसेंटिव इत्यादि देने का प्रावधान किया जाएगा।

हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये बनाए जाएंगे 1 लाख घर

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये 1 लाख घर बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिये ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने तथा इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
- इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण के लिये नई पैक्स नीति तैयार करने तथा एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पाँच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिये।
- यह एक अलग मॉडल है, जो उन लोगों को सक्षम करेगा, जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है। एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार की जाएगी।
- नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष पचास में शामिल करने के अलावा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी।
- राज्य स्तर पर 50 प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ रखने के प्रयासों के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में एक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

नोट :

- राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी ज़मीनों के मुद्रीकरण के लिये परियोजनाओं हेतु खाली पड़ी ज़मीनों को बेचने तथा वैल्युएबल भूमि उपयोग के लिये बाहरी परिधि पर वैकल्पिक ज़मीन खरीदी जाएगी।
- राज्य में सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय क्रमश: 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा, कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिये खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये।
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित होने वाली 'खिलाड़ी बीमा लाभ योजना', जो चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी, को अधिसूचित किया जाएगा।

डॉ. विजय चावला की टीम ने बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में जीते 3 अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में हरियाणा के कैथल ज़िले के ग्योंग के आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक डॉ. विजय चावला व उनकी टीम ने बाल शैक्षिक ई-सामग्री तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिये 3 अवॉर्ड जीते हैं।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कँवरपाल ने बताया कि डॉ. विजय चावला व उनकी टीम ने लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर हरियाणा का नाम रोशन किया है।
- अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता में पूरे भारत से 657 प्रविष्टियाँ आई थीं, जिनमें से कुल 77 प्रविष्टियाँ ही अवार्ड के लिये चयनित हो पाईं।
- हरियाणा शिक्षा विभाग से राष्ट्रीय नवाचारी अवार्डी शिक्षक डॉ. विजय चावला ने आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से चार प्रविष्टियाँ भेजी थीं। इन चार में से उनकी तीन प्रविष्टियों को अखिल भारतीय स्तर के अवार्ड के लिये चुना गया है।
- इस प्रतियोगिता में डॉ. चावला द्वारा तैयार 'निपुण भारत मिशन' के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता के सीखने के प्रतिफलों को इंटरैक्टिव तथा इंफोग्राफिक तकनीक से विकसित करने वाले कार्यक्रम को अवार्ड मिला है।
- इसके अतिरिक्त, दूसरा अवार्ड उनके द्वारा तैयार डिजिटल खेलों के माध्यम से हिन्दी व्याकरण की दक्षताओं के आकलन कार्यक्रम में विद्यार्थी हिमांशु के खेलों को बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड मिला है।
- तीसरा अवार्ड निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तैयार कहानी 'समझदार चिड़िया'कार्यक्रम में छात्रा रितिका को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कठपुतलियों का सफल प्रयोग करने हेतु बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है।
- विदित है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को राज्य में 2025 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य तय किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक लागू किया जाएगा।

नोट :

हिसार को मिली 19742.49 लाख रुपए की 93 परियोजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के साथ हिसार ज़िले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार ज़िले के नलवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 1552.04 लाख रुपए से बने हिसार-मंगाली-स्याहड़वा फोर लेन मार्ग, 4781.78 लाख रुपए की लागत से बने हिसार-मंगाली-स्याहड़वा आरओबी तथा 2796 लाख रुपए की लागत से बने रेवाड़ी-बठिंडा रेलवे लाइन एलसी-76 पर टू-लेन आरओबी का उद्घाटन किया। इन तीनों परियोजनाओं पर 9129.82 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।
- उकलाना विधानसभा क्षेत्र में 2622.09 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाले 8 सड़क मार्गों का व विधानसभा क्षेत्र बरवाला में 2424.67 लाख रुपए के 10 सड़क मार्गों का शिलान्यास भी किया गया।
- विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिये जिन परियाजनाओं के लिये करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, उनमें नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 2612.31 लाख रुपए की पाँच परियोजनाएँ, नलवा विधानसभा क्षेत्र में 2510.290 लाख रुपए की 17 परियोजनाएँ व आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 2636.12 लाख रुपए की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
- इन परियोजनाओं के शिलान्यास के अतिरिक्त महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के लिये आपातकालीन रास्ते तथा पैरीमीटर सड़क के निर्माण तथा परिचालन क्षेत्र में विस्फोटक निपटान क्षेत्र का निर्माण (कूलिंग ऑफ पिट) और आरसीसी सुरक्षा वॉच टॉवर के निर्माण कार्यों पर भी 2627.88 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।

नोट :